

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 85/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/146

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

खीमाराम पुत्र दानाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी मंडापुरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

- 1.पोनीदेवी पुत्री तगाराम
- 2.भगवानाराम पुत्र तगाराम
- 3.भीखीदेवी पत्नी तगाराम
- 4.लीलादेवी पत्नी तगाराम
- 5.सुजाराम पुत्र तगाराम
- 6.हवादेवी पुत्री तगाराम
जाति सुथार निवासी आकड़ली धनसिंह
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
- 7.गौतमचंद पुत्र भंवरलाल जाति माली
- 8.लक्ष्मण पंवार पुत्र राजूराम जाति माली
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
- 9.जगदीश पुत्र धंमड़ाराम
जाति खारोल (खारवाल)
निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा
- 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थिति-

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 23.07.24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिसे प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावे।

4. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्ड खातेदार है और रिकॉर्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.3.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होता प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) वालोतरा

हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर विप्रार्थी को आपत्ति नहीं है। यदि होती तो उजर-एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।


6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 23.7.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा